सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना

558.**श्री राम जेठमलानी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 158 बड़ी तथा 226 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निष्पादन के लिए तथा 95 सिंचाई परियोजनाएं पुररूद्वार हेतु लम्बित पड़ी थीं और इनके पूरा होने के लिए 40,000 करोड़ रूपए की धनराशि की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है,जिनका कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा हो जाने की संभावना हैं; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है,जिनके नवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा होने हेतु लम्बित रहने की संभावना हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) जी,हां । 158 बृहद,226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं 40,563 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 8वीं योजना में आगे ले जाई गई थी । आठवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं के लिए अन्य कई स्कीमों (14 बृहद,15 मध्यम और 24 विस्तार/ नवीकरण/आधुनिकीकरण स्कीमें)के लिए 22,415 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था । आठवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर 20,720 करोड़ रूपए का व्यय होने की संभावना है ।

(ग) 38 बृहद,100 मध्यम और 45 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं आठवीं योजना के दौरान पूरा किए जाने की संभावना हैं ।

(घ)बृहद,176 मध्यम और 74 विस्तार/नवीकरण आधुनिकीकरण परियोजनाएं नवीं योजना में जारी रहने की संभावना हैं ।

योजना आयोग के अनुमोदन हेतु लंबित सिंचाई परियोजनाएं

559.**श्री राम जेठमलानी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब तक अनेक मझोली तथा बड़ी परियोजनाओं के निर्माण का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां,तो विभिन्न क्षेत्रों में इन परियोजनाओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन स्वीकृत परियोजनाओं में से ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है,जो अप्रैल,1996 तक मूल समयानुसार पूरी हो गई थी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर सिंह): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित और मार्च,1996 तक पूर्ण वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्र है ।

विवरण

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित और मार्च,1996 तक पूर्ण वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या नीचे लिखे अनुसार हैं :-

क्र.स.	राज्य	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या वृहद	मध्यम	वृहद	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या मध्यम
1.	आंध्र प्रदेश	8	54	1	39
2.	असम	7	13	2	7
3.	बिहार	27	68	17	48
4.	गुजरात	21	86	10	68
5.	हरियाणा	7	-	4	-
6.	हिमाचल प्रदेश	-	4	-	3
7.	जम्मू और कश्मीर	-	15	-	9